अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत से करोड़ों का घोटाला

करनाल : धीरज, प्रवीण: स्थानीय डी एफ एस सी कार्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों की मिली भगत से कई राईस शैलटरों के मालिकों द्वारा करोड़ों रूपये की धांधली करने के सनसनीखेज समाचार सामने आ रहे है।

मिली जानकारी के अनुसार डी एफ एस सी महकमें और राईस शैलरों के मालिकों की मिली भगत से नई कम्पनी की आड़ में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ झाला किया जा रहा है । इस बारे में सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 2013-14 में डी एफ एस सी कार्यालय ने बड़े पैमाने पर डिफाल्टर मिल मालिकों पर कानूनी शिकंजा कसा था, जो सरकार द्वारा दिये गये चावल को हड़प कर सरकारी पैसों पर मौज कर रहे थे । जानकारी मिली है कि इनमें से कुछ डिफाल्टर मिल मालिक आज तक जेल काट रहे है। इनमें से एक कुलदीप बिश्नोई की उस समय की पार्टी हजकां की टिकट पर करनाल से विधान सभा चुनाव भी लड़ा था ।

सूत्रों का कहना है कि तत्कालीन डी एफ एस सी मलिक के वृदहस्त के चलते डिफाल्टर मिल चालकों को न केवल बचाया गया अपितु ऐसे डिफाल्टर मिल संचालकों को बा-दस्तूर कम्पनी का नाम बदल कर सरकारी चावल देना जारी रखा जो खेल आज तक जारी है, इस बारे में प्रकाश डालते हुये सूत्रों ने बताया कि इन डिफाल्टर मिल सचांलकों में से एक मिल संचालक जो कि 2013-14 से ही 32 हजार किवन्टल चावल का डिफल्टर घोषित हो चुका है आज भी अलग नाम से कम्पनी बना कर सरकारी लाभ प्राप्त कर रहा है । सूत्रों का कहना है कि लगभग 11 करोड़ रू की देनदारी के बावजूद डी एफ एस सी महकमा इस मिल मालिक पर मेहरबान बना हुआ है । ऐसा क्यों है इसका अन्दाजा सहज ही लगाया जा सकता है ।

सूत्रों का दावा है कि इस सारे भ्रष्टाचार के पीछे तत्कालीन डी एफ एस सी मलिक का हाथ है । सूत्रों का ये भी कहना है कि उपरौक्त तत्कालीन डी एफ एस सी मलिक ने कई डिफाल्टर मिल संचालकों के साथ बेनामी पार्टनशिप की हुई है । और मलिक ही है जो इन डिफाल्टरों को सरकार को चूना लगाने के नये-नये तरीके बताता है । ये भी दावा किया जा रहा है कि अगर हरियाणा सरकार उपरौक्त सारे प्रकरण की विजिलैंस द्वारा जाँच करवाये तो करोड़ों रू की लूट का पर्दाफाश हो सकता है। ये भी पता चला है कि जिस शैलर द्वारा 32 हजार किवन्टल चावल का डिफाल्ट किया गया है, इसी के ताऊ ने उसी स्थान पर एक अलग कम्पनी बनाई हुई है जहां पर डिफाल्ट हुआ है । महज कागजी खाना पूर्ति के लिये बीच में दिवार खींच दी गई है ताकि सरकारी चावल निर्विरोध मिलता रहे और कानूनी शिकंजे से बचा जा सके । जानकारी मिलने पर इस संवाददाता ने डी एफ एस सी कार्यालय में बातचीत की और डी एफ एस सी से दोनों मिलों की फाईल दिखाने का अनुरोध किया ताकि सच्चाई सामने आ सके तो डी एफ एस सी ने संवाददाता के सामने ही डीलिंग हैंड को फाईल दिखाने को कहा और ये भी कहा कि अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो सख्त कारवाई की जायेगी । लेकिन हैरानी इस बात की है कि डी एफ एस सी के दो बार निर्देश देने के बावजूद भी डीलिंग हैंड फाईलों पर कुण्डली मार कर बैठा है और हर बार कोई न कोई बहाना बना कर घोटाले को दबाने का प्रयास कर रहा है । अब देखने वाली बात ये है कि ईमानदार मुख्यमन्त्री की मनोहर सरकार इस पर क्या कारवाई करती है ।

व्यंग्य

गौवंश, पर्यावरण व स्वास्थ्य और समृद्धि हेतु पेट्रोल 500 रुपये प्रति लीटर होना जरूरी

पेट्रोलियम के बेतहाशा बढते भावों के पीछे संघ-भाजपा की विचारधारा यह समझी जा रही है कि इसके भाव जब जनता की क्रय शक्ति से बाहर हो जायेंगे तो लोग ट्रैक्टर की बजाय बैलों से खेती करेंगे। ट्रकों से माल ढुलाई की जगह बैलगाड़ियों का प्रयोग होगा, बसों व कारों की जगह घोडा गाड़ियां ले लेंगी। इससे जो आज गौवंश की बेकदरी हो रही है, व लावारिस घुरता फ़िर रहा है, उसकी मांग व कदर बढ़ेगी। गौ माता व उसके बच्चे कत्लखानों में जाने से बच जायेंगे। रही बात बीफ़ निर्यात से सैंकड़ों करोड़ डॉलर कमाने की तो वह काम भैंसों से ही चला दिया जायेगा।

जब बैलो से खेती होगी व बैलगाड़ियों से माल ढुलाई आदि होगी तो देश की जनता को बड़ी मात्रा में काम उपलब्ध होगा। अभी तो ट्रैक्टरों व मशीनों आदि से खेती करने के चलते बहुत थोड़े लोग तुरन्त काम को निपटा कर बैठ जाते हैं। जिससे बेरोज़गारों की फ़ौज दिन-प्रति दिन बढ़ती जा रही है। जाहिर है जब मशीनों के स्थान पर बैलों व घोड़ों का इस्तेमाल होगा तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को काम मिलेगा कि बेरोजगार ढूंढे से भी नहीं मिलेंगे। यानी कि बेरोजगारी की समस्या भी हल हो जायेगी। आज मोदीजी पर दो करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने का जो भार है वह स्वत: हट हो जायेगा।

पेट्रोलियम पदार्थों का इस्तेमाल ही नहीं होगा तो वायु प्रदुषण भी नहीं रहेगा। यानी पर्यावरण की समस्या भी समाप्त हो जायेगी। जब लोगों को प्रदुषण से मुक्ति मिल जायेगी तो लोग बीमार भी कम ही होंगे। ऐसे में सरकार के ऊपर पड़ा चिकित्सा का भार भी कम हो जायेगा। इससे सरकार को लाखों करोड़ की बचत होगी

जब तेल की कीमत आम लोगों की क्रय-शक्ति के बाहर हो जायेगी तो तेल का प्रयोग केवल चंद गिने-चुने बड़े पूंजीपति तथा सरकार व उसके अधिकारी लोग ही कर पायेंगे। इस वर्ग में शासक पार्टी व संघ के बड़े नेता भी शामिल रहेंगे। इन परिस्थितियों में स्वदेशी तेल से न केवल काम चलाया जायेगा बल्कि तेल का निर्यात भी किया जा सकेगा। आज जहां देश को खरबों डॉलर तेल का आयात करना पर रहा है इसकी जगह भारत तेल निर्यात से विदेशी मुद्रा कमाने लगेगा। जाहिर है डॉलर के मुकाबले गिरता रुपया डॉलर को भी पटकनी दे देगा। कोई बड़ी बात नहीं, आज जिस एक डॉलर के लिये 74 रुपये देने पड़ते हैं कल उसी एक रुपये की कीमत 74 डॉलर हो जाय।

मुंगेरी लाल के इन्हीं हसीन सपनों को चरितार्थ करते हुये राम राज्य तथा भारत की प्राचीनतम संस्कृति को लौटा कर लाने के लिये संघ पूर्णतया प्रयासरत है। अमितशाह एवं नरेन्द्र मोदी इन्ही सपनों को साकार करने में ही जी जान से जुटे हैं। अटल बिहारी बाजपेयी शासन काल के छ: साल व मोदी के पांच साल पूरे होने तक तो ये सपने अभी बहुत दूर हैं। इसलिये इन्हें अगले 50 साल का समय और चाहिये। राम-राम जय श्री राम।

'दुर्गा शक्ति' व महिला हेल्प लाइन 1091 केवल दिखावा

फ़रीदाबाद (म.मो.) खट्टर सरकार द्वारा महिला सुरक्षा हेतु बहु प्रचारित दुर्गा शक्ति व महिला हेल्पलाइन केवल दिखाने मात्र के लिए हैं। यह साबित हुआ दिनांक 11 सितम्बर की रात को जब 5एफ/40ए निवासी दिवांशी गुप्ता ने 1091 पर फोन कर पुलिस से सहायता मांगी।

शादीशुदा दिवांशी गुप्ता दिल्ली से अपने पिता दीपक बतरा का हालचाल जानने आई थी। उसे पता चला था कि उसके पिता व चाचा जसपाल की आपस में सिर फुटौव्वल हो गयी है। जब वह घर पहुंची तो उसके पिता बीके अस्पताल गये हुए थे। घर में उसकी छोटी बहन खुशबू जो स्कूल में शिक्षिका है, घर में अकेली थी। तभी जसपाल के दो बेटों- कमल व नितिन - ने घर में घुसकर दोनों बहनों की जमकर पिटाई कर दी व कपड़े फाड़ दिये। दोनों बहनों की हालत काफी बिगड़ गयी थी। दिवांशी ने खट्टर सरकार की बातों पर भरोसा करते हुए 1091 पर फोन करके सहायता मांगी। जवाब में कहा गया कि अभी 15 मिनट में सहायता पहुंच जायेगी।

लेकिन इसके करीब ढाई घंटे बाद रात को साढे दस बजे थाना एनआईटी से एसआई जीत राम का फोन आया कि वे दोनों महिलायें शिकायत लिखवाने खुद चलकर थाने आ जायें। डरी सहमी दोनों बहनें इस स्थिति में नहीं थी कि घर से निकल सकें। इसलिए उन्होंने डीसीपी (एनआईटी) को फोन लगा कर अपनी व्यथा बताई। इसके करीब आधे घंटे बाद यानि 11 बजे एसआई जीत राम दो सिपाही जिप्सी में लेकर आ गया और दोनों बहनों को अपने साथ अस्पताल चलने को कहा। बहनों ने पूछा महिला पुलिस कहां है? तो जीतराम ने कहा कि महिला पुलिस तो नहीं है। दिवांशी ने फिर से डीसीपी को फोन किया, डीसीपी ने जीतराम को कहा कि कहीं से भी महिला पुलिस का प्रबंध करे। अब बेचारा जीतराम कहां से महिला पुलिस पैदा करे जब थाने में पर्याप्त महिला पुलिस की तैनाती ही नहीं है।

खैर तब तक दिवांशी व खुशबू के पिता दीपक बतरा अस्पताल से लौट आये और वे खुद अपनी बेटियों को लेकर अस्पताल गये। तो यह है खट्टर सरकार की खटारा दुर्गा वाहिनी और महिला हेल्पलाइन। इस दौरान पुलिस वालों से दोनों बहनों को एक बहुमूल्य जान मुफ्त में यह प्राप्त हुआ कि दुर्गा वाहिनी केवल प्रात: 9.00 से सांय 5.00 बजे तक ही कार्य करती है। इसका मतलब साफ है कि पांच बजे के बाद पूरी रात महिलाएं दुर्गा वाहिनी एवम् महिला हैल्पलाइन के भरोसे न रहें।

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें:

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. **आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5**
2. **प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड**
3. **रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन**
4. **एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे**
5. **राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने**
6. **हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास**
7. **जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207**

गतांक की चीर-फ़ाड़

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

लोकतंत्र में अपनी मांगों को सुनवाई के लिये धरना देने व प्रदर्शन करने का सबको अधिकार

मज़दूर मोर्चा के 09-15 सितम्बर 2018 के अंक में राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक मुद्दों पर समाचार प्रकाशित हुए है। समाज में शराब माफ़िया, आबकारी विभाग व प्रशासन का गठजोड़ इतना गहरा है कि आम जनता की शिकायतों व परेशानियों की सुनवाई कराना टेढी खीर साबित होता है और शराब का ठेका किसी स्थान से हटवाना तो और भी कठिन हो जाता है, जिसका 'यारो माफ़ करना आवकारी विभाग नशे में है-फ़रीदाबाद में 10 सोसायटियों के लोग सेक्टर 48 में शराब का ठेका हटवाने के लिये दस दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, प्रशासन सो रहा है' में खुलासा किया गया है।

सेक्टर 48 में सैनिक कॉलोनी की बजाय गीता सोसायटी के सामने शराब ठेकेदार ने शराब का सेल और अहाता बना रखा है जहां पास ही में मंदिर, मस्जिद व स्कूल भी है जो शराब का ठेका खोलने के लिये आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित नियमों की खुली अवहेलना है। महिलाओं व बच्चियों का यहां से गुजरना दुश्वार हो गया है क्योंकि शराब पीकर लोग उन पर फब्तियां कसते हैं। इसलिये इस ठेके को यहां से हटवाने के लिये यहां के निवासी व सामाजिक कार्यकर्ता एकजुट होकर संघर्ष कर रहे हैं, परंतु आबकारी विभाग व प्रशासन के कानों पर जूं भी नहीं रेंगती। ऐसा लगता है कि उन्हें शान्तिमय प्रदर्शन व संघर्ष की कोई परवाह नहीं है।

जब-जब चुनाव आते हैं तो भाजपा अपने तरकश में से बोफ़ोर्स की तरह हुड्डा-वाड्रा के भूमि घोटाले का तीर निकाल लेती है। यदि वास्तव में भाजपा हुड्डा-वाड्रा को भूमि घोटाले में मुकदमा चलाकर उन्हें जेल भेजना चाहती तो आइएएस अधिकारी अशोक खेमका की रिपोर्ट के आधार पर 2014 में उन पर एफ़आईआर दर्ज करा सकती थी, जो अब सुरेन्द्र शर्मा की शिकायत पर किया गया है, जिसका 'हुड्डा वाड्रा पर मुकदमा

दर्ज, बहुत देर कर दी सनम आते-आते' में विवेचन किया गया है। वास्तव में खट्टर सरकार ने कोई कार्यवाई करने की बजाए इस घोटाले को चुनावी मुद्दा बनाए रखने के लिये टाइम पास किया जिसका लाभ अभियुकतों को अदालत में मिलने की आशंका है।

एनएच-3 स्थित डीएवी मैनेजमेंट कॉलेज में घोटालों व बदहाली की रिपोर्ट मज़दूर मोर्चा के अंकों में प्रकाशित हो रही है, परन्तु कॉलेज प्रबन्धन समिति, डीएवी मैनेजमेंट कमेटी, दिल्ली, एआईसीटीई (ऑल इन्डिया काऊंसिल ऑफ़ टेक्निकल एजुकेशन) तथा एमडीयू (महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी) इसकी ओर अपनी आंखे मूंद बैठी है, जिसका 'खुद अपना प्रबन्धन नहीं कर सकता डीएवीआईएम, छात्रों का क्या पढायेंगे' में पूरा कच्चा चिट्ठा खोला गया है। डीएवी जैसी प्रतिष्ठित संस्था में नीलम गुलाटी को येन-केन प्रकारेन प्रिंसिपल बनाने के लिये नियमों को ताक पर रखकर हर प्रकार अनैतिक हथकंडे अपनाये जा रहे हैं, जो डीएवी जैसी संस्था के लिये निंदनीय है।

लोकतंत्र में अपनी मांगों को सुनवाई के लिये धरना देने व प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है। परंतु स्थानीय नेहरू कॉलेज के सामने धरना व प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांगों को मानने या सुनवाई करने की बजाए खट्टर सरकार की पुलिस व लड़कियों की सुरक्षा के लिये गठित दुर्गा शक्ति वाहिनी दल ने छात्रों को पीटा व लड़कियों को बालों से पकड़कर घसीटा, जिसका 'बात करने का वक्त नहीं, पुलिस है न लाठियां मारने को!' में असलियत से रूबरू कराया गया है। ध्यान देने योग्य बात है कि छात्र न तो नौकरी मांग रहे थे न कोई भत्ता, इनकी मुख्य मांगे है फ़रीदाबाद में एमडीयू का रीजनल सेंटर बनाया जाए, सरकारी कॉलेजों में मूलभूत सुविधायें तथा स्टाफ़ पूरा किया जाए आदि। भारत का विश्व गुरू बनाने का सपना दिखाने वाले मोदी और ईमानदारी व पारदर्शिता का ढोंग करने वाले खट्टर के लिये ये नितांत शर्मनाक है कि जो सरकार को बिना मांगे देना चाहिये उसके लिये लोकतंत्र में एक माह से ऊपर हुये धरने पर बैठे छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करवाया जाए।

मज़दूर मोर्चा के 02-08 सितम्बर 2018 के अंक में आरएसएस और मुस्लिम ब्रदरहुड की कार्यशैली और अल्पसंख्यकों के प्रति उनके नजरिये आदि लेकर दोनों में समानताओं की विवेचना की गई थी। दोनों ही नवउदारवादी हैं तथा दोनों की कॉरपोरेट जगत से गहरी दोस्ती है। परन्तु भारतीय समाज की शांति के लिये आरएसएस एक बड़ा खतरा है जो भारत में अपने आप में कानून बना हुआ है और भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक हिन्दुत्व को फ़ासिस्ट रंग देने की कोशिश में है, जिसका 'खबर (दार) झरोखा। मुस्लिम ब्रदरहुड से बड़ी चुनौती है आरएसएस की' में सटीक विश्लेषण किया गया है।

मोदी सरकार द्वारा फ्रांस से किये गये राफ़ेल डील विवाद में मोदी सरकार तथा स्वयं प्रधानमंत्री मोदी चारों ओर से घिर गये हैं। सरकार गोपनीयता व सुरक्षा की आड़ में राफ़ेल लड़ाकू विमान की कीमत, अनिल अम्बानी की कम्पनी रिलायंस डिफेंस आदि का खुलासा करने को तैयार नहीं है। सरकार ने अपने बचाव में टीवी अभिनेत्री पल्लव जोशी, वित्त मंत्री अरूण जेटली आदि को आगे कर दिया और अब बचाव में वायु सेना प्रमुख बी.एस. धनुआ को आगे कर दिया। बचाव में सैनिक अधिकारियों को आगे करना सरकार के लिये ठीक नहीं है। विशेष बात यह है कि इन लोगों को डील के बारे में कोई जानकारी नहीं है।'मोदीजी सचमुच चमत्कारी हैं, जानिए कैसे ?-राफ़ेल डील:समझौते से 12 दिन पहले बनी रिलायंस कंपनी के पास न लाइसेंस था और न ही जमीन और बिल्डिंग' में रिलायंस डिफेंस कंपनी व राफ़ेल डील की असलियत का पूरा खुलासा किया गया है। चर्चा है कि अनिल अम्बानी की तरह मोदी सरकार ने एचएएल को दर किनार करते हुये गौतम अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिये पिछले महिने स्वीडन से 100 विमान खरीदने का सौदा किया है।

भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में पुलिस जांच में हिंदुत्ववादी संगठनों के मिलिंद एकबोते और संभाजी भिड़े हिंसा के दोषी पाये गये थे तथा पानसरे, दाभोलकर, कुलबर्गी व गौरी लंकेश की हत्या में एसआईटी की जांच में सनातन संस्था का नाम उजागर हुआ था परन्तु अब अर्बन नक्सली के नाम से पांच प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार करने के बाद मोदी सरकार ने मीडिया व लोगों का ध्यान अर्बन नक्सलवाद की तरफ़ मोड़ दिया और हिन्दुत्ववादी संगठनों के विरुद्ध जांच को आगे बढाने की ओर किसी का ध्यान नहीं है।'भीमा कोरेगांव मामले में पुलिस को लताड़', 'जेएनयू नक्सली और आतंकवादी मुझे मार देंगे: पीएम मोदी-मैंने नक्सली और आतंकवादी को समाप्त करने का संकल्प लिया: सीएम मोदी' तथा 'सुधा की गिरफ़्तारी को एसपीजी टेस्ट से गुजारना चाहिये' में मानवाधिकार व सामाजिक कार्यकर्ताओं की मोदी सरकार द्वारा गिरफ़्तारी की साजिश का कच्चा चिट्ठा खोला गया है। आरएसएस, भाजपा तथा मोदी अंधभक्त लोग मोदी सरकार की कार्यवाई का खुला समर्थन करते हैं और बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि एनजीओ, वामपंथी और प्रोफ़ेसर, पत्रकार व लेखक नक्सलवाद के समर्थक व पोषक हैं तथा जेएनयू नक्सलवाद का गढ़ है जहां प्रोफ़ेसर लड़कों को ब्रेनवाश करके उन्हें नक्सली बनाते हैं। लोकतंत्र के नाम से वे देश में आतंक का राज्य स्थापित करना चाहते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपनी रैलियों में बात करते हुये हाथ पर हाथ मारकर श्रोताओं को रिझाने की कोशिश करने पर' भारत के लोग भी गजब शौक रखते हैं, मनोरंजन के लिये प्रधानमंत्री ही रख लिया है' तथा पैट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों पर 'चालान ही काट दो ....अपनी-अपनी गाड़ियों से जाते तो जितने का पेट्रोल लगता उससे तो सस्ता ही पड़ेगा!' कार्टूनों द्वारा मोदी की शैली व नीतियों पर उपयुक्त व्यंग्य किया गया है।